मंत्री व विधायक सदन में बेहतर उपस्थिति व सक्रिय भूमिका निभाएं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक में अनुशासन व समयबद्धता पर जोर दिया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक ली।

- **भाजपा विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे का निर्धारित था। बड़ी संख्या में मंत्री व विधायक समय पर नहीं पहुँच पाये, इसलिए बैठक निर्धारित समय पर शुरु नहीं हो पाई। पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बैठक स्थल पर समय पर पहुँच गए थे।**

जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक विधानसभा परिसर की सत्ता पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। बैठक के शुरू में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाणा और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बेहतर उपस्थिति और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का है और इसकी कार्यवाही का पूरा सदुपयोग जनहित में किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्थान के लिए रेलवे क्षेत्र में किए गए 10 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का उल्लेख करते हुए इसे राज्य के बुनियादी ढ ांचे के लिए महत्वपूर्ण बताया। विधायक दल की बैठक को लेकर एक अहम मुद्दा भी सामने आया। बैठक का समय सुबह 10 बजे निर्धारित था, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। तथापि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं समय पर बैठक स्थल पर पहुंच गए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि यदि सभी मंत्री और विधायक समय पर बैठकों में पहुंचेंगे, तो चर्चा भी समय पर और अधिक प्रभावी ढ ंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समयबद्धता सरकार की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और इसे हर स्तर पर अपनाया जाना चाहिए।

'प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्व बढ़ाने की गलत नीयत से लागू किया है, जो छोटे खनन लीज़धारकों की कमर तोड़ने जैसा है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1975 से 2010 तक जी.टी. शीट्स के आधार पर खनन क्षेत्रों की सीमाएं (बाउंड्री) तय की जाती थीं। इसके बाद खनन विभाग ने जी.टी.शीट्स को "गूगल अर्थ" से ली गई तस्वीरों पर अपलोड कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया से भी कई जगहों पर वास्तविक जमीन स्थिति से करीब 100 मीटर दूरी तक का अंतर था। इस कारण भी कई लीज़ धारकों के बीच विवाद सामने आया था। अब जो ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का नियम लागू किया जा रहा है, उससे भी करीब 15-20 मीटर दूरी तक का अंतर सामने आ रहा है। इस समस्या का भी खनन विभाग की ओर से कोई समाधान मुहैया नहीं करवाया जा रहा।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और खनन विभाग सिर्फ ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही लीज़धारकों पर जुर्माना तय करके पैनल्टी लगा रहे हैं। यह इसलिए अव्यवहारिक है, क्योंकि ड्रोन सर्वे के आधार पर ही यह तय नहीं किया जा सकता कि किस ब्लॉक में वास्तविकता में कितना खनन किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किस खनन लीज़ से कितनी मात्रा में बजरी अथवा अन्य पत्थर निकलेगा, इसका मापदंड भी तय नहीं है। ऐसे में ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पैनल्टी किस प्रकार लगायी जा सकती है।

'मुझे नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके साथ ही, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें से एक वाम दल का सदस्य भी शामिल है।

लेकिन, नरेन्द्र मोदी तमाम आलोचनाओं के बावजूद अप्रभावित दिखे। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में स्वयं को माला पहनवाई, और दिन भर टीवी चैनलों पर मोदी, ट्रम्प और इस ट्रेड डील की तारीफों का दौर चलता रहा कि उन्होंने कितना शानदार काम किया है।

सवाल यह है कि जब विपक्ष के इतने नेता मोदी का सीधे सामना करने और यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि उन्होंने देश को बेच दिया है, तब राहुल गांधी में ही यह साहस है कि वे सीधे नरेन्द्र मोदी पर हमला करें और गलत को गलत कहें।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को एन.एस.यू.आई. की ओर से आयोजित "युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरूद्ध" कार्यक्रम में शामिल हुए।

अमेरिका तय नहीं कर सकता भारत की विदेश नीति- पायलट

वे एनएसयूआई के "युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरूद्ध" में शामिल होने जयपुर आए

- **कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता।**

जयपुर (कासं), 3 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील, विदेश नीति, टैरिफ, लोकतंत्र और बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं चल सकती। यह भारत का अधिकार है कि वह किस देश से तेल खरीदेगा, अमेरिका यह तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल न खरीदे और वेनेजुएला से खरीदे। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। पायलट ने ये बातें मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से रूबरू होकर कही।

पायलट, एन.एस.यू.आई. की ओर से विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित "युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरूद्ध" कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आए थे। उनके साथ एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनियां, विधायक प्रशांत शर्मा, दीनदयाल बैरवा, पूर्व विधायक गजराज खटाना, वेदप्रकाश सोलंकी, राकेश पारीक, कांग्रेस नेता अनिल चौपड़ा, वीजीयू के चेयरमैन डॉ. के.आर.बगरिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले टैरिफ औसतन 5 से 7 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया गया और अब घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। पायलट ने इसे भारत पर दबाव बनाने की राजनीति बताया।

केन्द्र सरकार के बजट पर निराशा जताते हुए पायलट ने कहा कि इसमें राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता है।

'भारत-अमेरिका ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसका कहना है कि अमेरिका अक्सर ताकतवर स्थिति से बातचीत करता है और अन्य मामलों में उसने ऐसे समझौते हासिल किए हैं, जिनसे साझेदार देशों के बाज़ार खुले तथा घरेलू नियमों में ढील आई और अमेरिकी निर्यातकों को भारी लाभ मिला। छोटे देशों के साथ हालिया अमेरिकी व्यापार समझौतों का उदाहरण देते हुए जीटीआरआई ने तर्क दिया कि किसी भी भारत-अमेरिका समझौते को वास्तव में पारस्परिक होना चाहिए और केवल अल्पकालिक शुल्क कटौती पर केन्द्रित होने के बजाय, भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

कृषि चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या हटाने से भारतीय किसानों को भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी अनाज, डेयरी और पोल्ट्री से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उसने यह भी आगाह किया कि शुल्क संरक्षण की जगह ढीले नियामकीय प्रावधान, जिनमें स्वच्छता और फायटोसैनिटरी मानक शामिल हैं, अपनाने से खाद्य सुरक्षा मानक कमज़ोर हो सकते हैं और वे सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से संवेदनशील सुरक्षा उपाय खत्म हो सकते हैं, जिन्हें एक बार छोड़ देने के बाद बहाल करना कठिन होता है।

निर्यात के मोर्चे पर, जीटीआरआई ने वस्त्र, आभूषण, झींगा और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊँचे शुल्कों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। उसका तर्क है कि सुनिश्चित और टिकाऊ बाज़ार पहुँच के बिना भारत शुल्क में रियायतें दे सकता है, जबकि उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती जाए। शुल्क से आगे बढ़कर, थिंक टैंक ने बार-बार नियामकीय संप्रभुता की रक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया है और चेतावनी दी है कि बाध्यकारी व्यापार प्रतिबद्धताएँ भविष्य के आर्थिक या भू-राजनीतिक बदलावों के अनुरूप नीतियों को पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती हैं।

अंत में, जीटीआरआई ने अमेरिकी प्रणाली के भीतर मौजूद कानूनी और राजनीतिक जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। उसका कहना है कि व्यापार प्रतिबद्धताओं में कांग्रेस द्वारा बदलाव लाया जा सकता है या उन्हें कमज़ोर किया जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब फास्ट-ट्रैक प्राधिकरण न हो। इससे एक असंतुलन पैदा होता है, जिसमें भारत की रियायतें स्थायी हो जाती हैं, जबकि अमेरिकी दायित्व घरेलू राजनीतिक उठापटक के अधीन रहते हैं। कुल मिलाकर, जीटीआरआई की आलोचना अस्वीकृति से अधिक सतर्कता पर आधारित है और इस बात पर ज़ोर देती है कि एक टिकाऊ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों, उद्योग और नीतिगत स्वायत्तता की रक्षा करे, न कि अमेरिका को भारी लाभ पहुँचा दे।

आज सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण लोगों को हो रही "भारी असुविधा और पीड़ा" पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के चलते पूरे राज्य में "लगभग 140 मौतें" हुई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर मौजूदा कानूनों का खुला उल्लंघन करते हुए और "मानवाधिकारों तथा बुनियादी मानवीय संवेदनाओं की पूरी तरह अनदेखी" के साथ संचालित की जा रही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 8,100 माइक्रो ऑब्ज़र्वर्स तैनात किए हैं।

उन्होंने इस तैनाती की आलोचना करते हुए कहा कि माइक्रो ऑब्ज़र्वर्स को, बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और सिद्ध विशेषज्ञता के, एकतरफा तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह एक "विशेषीकृत, संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया" है।

ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा, "मैं एक बार फिर उस कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को लेकर लिखने के लिए विवश हूँ, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से परे जाकर, पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है।"

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका सूचीबद्ध होने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब आगामी चुनावों से पहले राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका फैसला एसआईआर की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल में व्यापक चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकता है।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह मामला 4 फरवरी को सूचीबद्ध होने की संभावना है और यदि सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री के स्वयं पीठ के समक्ष उपस्थित होने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया। इसके बदले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश को लगभग 3 करोड़ रुपए राजस्व राशि के रूप में भुगतान किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश आयोग के निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, सचिव दीपक सिंह और राजस्थान आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों देश दवाइयों, स्टील, विमानों, तकनीकी उत्पादों और कुछ कृषि वस्तुओं सहित, कई तरह के उत्पादों का पहले से व्यापार कर रहे हैं। सालाना व्यापार का आकार लगभग 130 अरब डॉलर था, जो न तो बहुत कम था और न ही बहुत ज़्यादा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच अचानक घोषित ट्रेड डील से ट्रम्प को ज़रूर झटका लगा होगा।

रूसी तेल खरीदने पर भारत को दंडित करने के अपने फैसले की मूर्खता का एहसास ट्रम्प को तब हुआ होगा, जब उन्होंने देखा कि भारत और ईयू ने लंबे समय से चल रही द्विपक्षीय व्यापार रूपरेखा पर बातचीत को तेज़ी से पूरा कर लिया। आखिरकार यह अजीब ही था कि अमेरिका यूरोप में चल रहे किसी और के युद्ध के लिए भारत को सज़ा दे रहा था, जबकि जो देश वास्तव में रूस से युद्ध के ख़तरे का सामना कर रहे हैं (यूरोपीय देश), वे खुशी-खुशी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं।

यह समझते हुए कि वह किस स्थिति में फँस गए हैं, ट्रम्प ने फिर एक चाल चली, उन्होंने एकतरफ़ा तौर पर एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा कर दी और साथ ही रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को भी एकतरफ़ा रूप से हटाने का ऐलान कर दिया।

"डैड ट्रम्प" की इस अचानक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के सामने प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उन्हें इस घोषणा का स्वागत करना ही पड़ा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया की भलाई के लिए डॉनल्ड ट्रम्प के साथ काम करना कितना सुखद है।

यह पूरा मामला एक बेतुके नाटक का हास्यास्पद तमाशा लगता है। तथाकथित व्यापार समझौते के दोनों पक्ष अब भी अस्पष्ट बने हुए हैं।

व्यापार समझौता एक गंभीर विषय होता है और इसमें शामिल देशों पर इसके दूरगामी असर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस यह कह दिया जाए कि सभी टैरिफ हटा दिए गए हैं और सामान बिना किसी रुकावट के आएगा-जाएगा। व्यापार समझौतों में शुल्क संरचनाओं, टैरिफ उद्देश्यों के लिए माल की श्रेणियों और सबसे अहम घरेलू घटक (डोमेस्टिक कंटेंट) से जुड़े विस्तृत प्रावधान होते हैं। ये बातें एक फोन कॉल के तुरंत बाद तय नहीं की जा सकतीं और आमतौर पर पेशेवर लोग इन्हें लंबे समय में तैयार करते हैं।

- **पर, इस अव्यवहारिक शर्त के अंतर्गत भी व्यापारिक संतुलन बिठाना बहुत कठिन है। भारत, अमेरिका को कम मूल्य के लेवर "इन्टैसिव" प्रोडक्ट्स बेचता है और उनका उत्पादन अचानक एक झटके में बढ़ाना संभव नहीं। जबकि, भारत अगर कुछ हवाई जहाज अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदता है तो अमेरिका का भारत के निर्यात का आंकड़ा अचानक बहुत जल्दी आसमान छूने लगेगा।**
- **ट्रंप द्वारा अचानक "ट्रेड डील" की घोषणा करने के कुछ भी कारण हों, पर, भारत के लिए इस डील का अचानक आना और कुछ नहीं, तो एक "डिप्लोमैटिक" (कूटनीतिक) कामयाबी तो जरूर है ही।**

डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा के बाद, इनमें से किसी भी मुद्दे पर शायद ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

जैसा कि ट्रंप ने वादा किया है, रूसी तेल की भारतीय खरीद में कमी के वादे का शायद ही कोई संकेत है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बजाय वेनेज़ुएला का कच्चा तेल खरीदेगा, जो प्रकृति में रूसी तेल जैसा है और इसलिए भारतीय रिफाइनरियाँ इसे आसानी से अपना सकती हैं।

मान भी लें कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल की जगह वेनेज़ुएला का तेल स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर भी वेनेज़ुएला के पूरे तेल उद्योग का उत्पादन भारत की ज़रूरतों के सामने बहुत कम है। भारत कच्चे तेल का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्टों के अनुसार, वेनेज़ुएला के तेल उद्योग का कुल उत्पादन भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले तेल से कहीं कम है।

मान लें कि वेनेज़ुएला का तेल उपलब्ध भी हो, तो उसे समुद्र के रास्ते भारत तक लाना अपने-आप में एक बहुत बड़ा काम है, और वेनेज़ुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुँचने से पहले इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी।

सबसे बढ़कर, भारत द्वारा अचानक रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करने के रणनीतिक प्रभाव भी हैं। भारत रूसी हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर काफ़ी हद तक निर्भर है।

फिर ट्रेड एग्रीमैंट के बारे में एक बुनियादी बात है, जिसका दावा ट्रम्प कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत ने अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ शून्य करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि अमेरिका कम से कम 18 प्रतिशत टैरिफ बनाए रखेगा। अगर भारत ने ऐसा कोई भी वादा किया है, तो यह बेहद असामान्य होगा। कोई भी देश दूसरे देश से इसी तरह की छूट के बिना सामानों पर शून्य शुल्क की अनुमति नहीं दे सकता। भारत यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अमेरिकी सामान बिना किसी शुल्क के आए, जबकि उसके अपने उत्पादों पर अमेरिका 18 या अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्यूटी लगाए।

यह अपनी आर्थिक संप्रभुता छोड़ने जैसा होगा। इसे किसी भी तरह से मुक्त व्यापार समझौता नहीं कहा जा सकता। पिछले एक साल में दोनों पक्षों के बीच कई दौर की व्यापार बातचीत हो चुकी है, और व्यापार विशेषज्ञों ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए होंगे।

स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए, इन्हें उचित तरीके से घोषित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रम्प ने 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य घोषित किया है। सन् 2030 तक न सही, लेकिन इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार और कुल जीडीपी को देखते हुए इतना बड़ा व्यापार लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर भारत अपने घरेलू नागरिक उड्डयन बेड़े के लिए बोइंग कंपनी से कुछ विमान खरीदता है, तो अमेरिका से आयात का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ जाएगा।

लेकिन भारत के लिए अमेरिका को निर्यात बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। भारत आमतौर पर कम मूल्य वाले उत्पाद, जैसे कपड़ा, चमड़ा, श्रम-प्रधान वस्तुएं, दवाइयां और इसी तरह के छोटे-छोटे मूल्य वाले उत्पाद निर्यात करता है। कम समय में इनकी बिक्री को तेजी से बढ़ाना मुश्किल साबित हो सकता है।

संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी कृषि उत्पाद भी इस व्यापार समझौते में शामिल हैं और ये अब भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक खतरनाक कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है, अगर भारत के किसान को उसके अपने ही देश में बाज़ार से बाहर कर दिया जाए।

चाहे जितने भी टैरिफ हटा दिए जाएं और अमेरिकी कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, रुपये और डॉलर की विनिमय दर को देखते हुए भारत में बड़े पैमाने पर अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद तब तक संभव नहीं है, जब तक अमेरिका इन्हें भारी सब्सिडी न दे। इसके अलावा, कृषि उत्पादों को लेकर हमारी पसंद भी अलग है और भारत शायद अधिकांश अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए तैयार बाज़ार नहीं हो सकता। किसी भी खरीद के मामले में उपभोक्ता की पसंद मायने रखती है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा के पीछे सच्चाई जो भी हो, कूटनीतिक रूप से यह भारत के लिए उपयोगी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम दंडात्मक टैरिफ अब स्थायी रूप से खत्म हो जाए।

11 फरवरी को होगा मुम्बई मेयर का चुनाव

6 फरवरी को नामांकन दाखिल होंगे तथा 11 फरवरी को नामांकन वापस लिए जाएंगे

- **लॉटरी प्रणाली के तहत मुम्बई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला को मिला है, इससे शिव सेना (उद्धव गुट) की उम्मीदें टूट गई हैं, वहीं भाजपा में भारी उठापटक मची है। मेयर बनने की आकांक्षी कद्दावर महिला पार्षदों ने जोड़तोड़ करना शुरु कर दिया है।**
- **इनमें रितु तावड़े, हर्षिता नर्वेकर व शीतल गंभीर प्रमुख हैं। पार्टी का एक धड़ा तावड़े के पक्ष में है, वहीं स्पीकर राहुल नर्वेकर अपनी भाभी हर्षिता के पक्ष में खड़े हैं।**
- **सबसे प्रमुख बात यह है कि इन तीनों को ही बाहरी बताया जा रहा है, क्योंकि ये अन्य दलों से भाजपा में आई हैं। पार्टी का एक गुट कह रहा है कि मेयर पद ऐसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने शुरु से ही मुम्बई में भाजपा के लिए काम किया हो।**

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 3 फरवरी। बृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बी एम सी) के मेयर पद का चुनाव 11 फरवरी को होगा और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि भी वही होगी।

इस समय-सीमा के तय होने से राजनीतिक दलों, विशेषकर देश के इस सबसे बड़े नगर निकाय में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा के भीतर, राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं।

इस वर्ष का महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कराई गई लॉटरी के ज़रिये लिया गया है। इस कारण जहां सत्तारूढ़ दल के भीतर ज़ोरदार लाबिइंग शुरू हो गई है, वहीं विपक्ष ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से तैयार की गई है।

भाजपा के भीतर महापौर पद की दौड़ ने विभिन्न गुटों के बीच मतभेद उजागर कर दिए हैं। पार्टी के नेता निजी तौर पर इसे पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य दलों से आए बाहरी लोगों के बीच संघर्ष के रूप में बता रहे हैं।

कई महिला पार्षद इस पद के लिए दावेदारी कर रही हैं और वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीते कुछ दिनों में लॉबिइंग तेज़ हो गई है। दावेदार और उनके समर्थक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मिलने का समय मांग रहे हैं, जिन्हें पार्टी के अंतिम फैसले में निर्णायक माना जा रहा है।

भाजपा के भीतर चर्चा में तीन नाम प्रमुख हैं : हर्षिता नरवेकर, ऋतु तावडे और शीतल गंभीर।

मुंबई भाजपा का एक गुट ऋतु तावडे के पक्ष में मज़बूती से खड़ा है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर अपनी भाभी हर्षिता नरवेकर की उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं।

इसी बीच, पार्टी के भीतर एक अन्य वर्ग ने आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि नरवेकर, तावड़े और गंभीर मूलरूप से भाजपा सदस्य नहीं हैं; वे अन्य दलों से आकर पार्टी में शामिल हुई हैं। इन नेताओं का कहना है कि महापौर का पद किसी ऐसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने वर्षों तक मुंबई में भाजपा संगठन के भीतर काम किया हो।

यह राजनीतिक उथल-पुथल उस घोषणा के बाद सामने आई है कि मुंबई का अगला महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह निर्णय राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा कराए गए लॉटरी ड्रॉ के ज़रिये लिया गया। यह विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास हैं।

लॉटरी प्रणाली यह तय करती है कि महापौर का पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा-सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)। श्रेणी घोषित होने के बाद ही पात्र पार्षद नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि लॉटरी ड्रॉ मुंबई सहित, महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निकायों के लिए किया गया, जहां 15 जनवरी को चुनाव हुए थे।

ड्रॉ का परिणाम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लिए झटका साबित हुआ। पार्टी को उम्मीद थी कि मुंबई का महापौर पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होगा। श्रेणी की दोनों पात्र महिला पार्षद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली इसी पार्टी से हैं।

पिछले सप्ताह आए नगर निकाय चुनाव नतीजों के बाद, ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से उम्मीद जताई थी कि "अगर भगवान चाहेंगे" तो मुंबई को उनकी पार्टी का महापौर मिलेगा। लेकिन ड्रॉ में यह पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद उनकी ये उम्मीदें टूट गईं। शिवसेना (यूबीटी) का आकलन था कि एसटी आरक्षण से उसे शीर्ष नागरिक पद पुन: हासिल करने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता था। यह पद पार्टी ने 1997, जब पार्टी विभाजित नहीं हुई थी, के बाद से लगातार 25 वर्षों तक संभाला था।

आईसीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूत्रों ने पुष्टि की है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्डों से पीसीबी को मिली प्रतिक्रिया काफ़ी सख़्त रही है। आम राय यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के पास कोई वैध आधार (कानूनी स्थिति) नहीं है। पीसीबी ने इस बहिष्कार को बाँग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद उसके साथ एकजुटता दिखाने के रूप में पेश किया है, लेकिन इसे एक बनावटी संकट के रूप में देखा जा रहा है।

सदस्य बोर्डों ने कई ऐसे विरोधाभासों की ओर इशारा किया है, जो इस कदम के पीछे पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला, बिना किसी विरोध या बहिष्कार की बात किए।

स्पष्ट असंगति का एक और उदाहरण यह है कि पाकिस्तान की महिला 'ए' टीम उसी दिन (15 फ़रवरी को) भारत 'ए' के खिलाफ खेलने वाली है और बैंकॉक में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 मैच से उसके हटने की कोई योजना नहीं है।

चूंकि पुरुष वर्ल्ड कप का मैच कोलंबो, श्रीलंका में एक न्यूट्रल जगह पर होना है, इसलिए बांग्लादेश द्वारा भारत यात्रा के बारे में बताई गई "सुरक्षा चिंताओं" का पाकिस्तान की स्थिति पर कोई लॉजिकल असर नहीं पड़ता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908